असम की हिंसा पर सहानुभूति से भी अधिक सोचने की जरुरत

- सुनील आंबेकर, राष्ट्रीय संगठनमंत्री
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

इस बार २० जुलाई से ही असम के बोडो क्षेत्र के हिंसाग्रस्त होने की बडी बडी खबरें आने लगी, लेकिन देश में अधिकतम लोगों के मन में उतनी बडी प्रतिक्रिया नहीं थी। असम हिंसा का दौर लगातार ही चल रहा है, तथा २००८ में भी बोडो क्षेत्र के उदालगुडी व अन्य क्षेत्र में हमले हुए तथा एक लाख से अधिक लोग पीडित शिबिरों में रहने पर मजबूर हुए थे। परन्तु इस बार जब दोनों तरफ झडपें चलती रही तथा घुसपैठियों को भी कुछ क्षेत्र छोडना पडा, तब उनके समर्थकों ने अपनी शकित का प्रदर्शन अन्यत्र प्रारंभ किया। विशेषकर मुंबई में 'अल्पसंख्यकों पर अत्याचार' के घोषवाक्य की आड में अवैध बांग्लादेशी घुसपंठियों के समथर्न में रजा अकादमी के तत्त्वाधान में हिंसक प्रदर्शन दि. ११ अगस्त २०१२ को आयोजित हुआ तथा बाद में देशभर में अध्ययन कर रहे छात्र या रोजगार में लगे हुए पूर्वोत्तर के लोगों को धमकाया गया तथा तत्काल अपने घर वापस जाने के लिए उन्ही घुसपैठियों के समर्थकों द्वारा मजबूर करने का प्रयास किया गया, परिणाम स्वरुप देश के प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, पुणे, हैदराबाद, राँची, बैंग्लोर आदि स्थानों से मुंबई के प्रदर्शन के तत्काल पश्चात् पूर्वोत्तर वापसी हेतु पलायन प्रारंभ हुआ। दोनो घटनाओं ने देशभर के लोगों को झकझोर कर रख दिया तथा घुसपैठीयों व उनके समर्थक किस हद तक जा सकते है, इसका भयंकर चेहरा उजागर हुआ। इन घटनाओं ने पूरे देश को हिला दिया तथा उस संकट की गंभीरता ने सभी की चिंता बढा दी।

घटनाओं को अलग – अलग देखने की जगह जोडकर देखने से साफ तौर पर षड्यंत्र दिखायी पडता है। विभाजन के पश्चात् लगातार बांग्लादेशी से सटी खुली या तटस्थ सीमा से लाखो घुसपैठियों ने अवैध तरीकों से भारत में प्रवेश किया। यह कई बार कहा जाता है कि वे लोग रोजगार की तलाश में यहाँ आते है। लेकिन यह जवाब कोई नहीं देता कि रोजगार के लिए वैध तरीके से आने का मार्ग उपलब्ध होने पर भी यह अवैध रास्ता क्यों अपनाया जाता है ?

घुसपैठियों को अवैध रुप से लाने वाले लोगों के एजेंट सीमा के दोनों तरफ उपलब्ध है। अवैध घुसपैठ द्वारा असम के क्षेत्र में जनसंख्या संतुलन अपने पक्ष मे करते हुए अंतत : असम को भारत से तोडने का यह षड्यंत्र है। १९४७ में हुए भारत विभाजन की पूर्व घटनाओं का क्रम जोडने से लगता है, जैसे वहीं बातें किसी सिक्वेल में बनी हिंदी फिल्म की तरह दोहरायी जा रही है और हम है कि अभी भी गूढ कहानी की तरह देख रहे है। एक – एक क्षेत्र को मुस्लिम बहुल बनाना, फिर वहाँ दहशत फैलाना, अन्य मूलरुप से स्थायी लोगों को वहाँ से दंगा करते हुए भगाना, अलग विशेष क्षेत्र की मांग, अल्पसंख्यक होने का दवा करते हुए अत्याचार से पीडित होने का दावा करना, अपनी मतदाता संख्या के आधार पर राजनैतिक दलों को लुभाना एवं सत्ता तथा प्रशासन पर दबाव बनाना एवं इस मार्ग में कई सारे अवैध कार्य जैसे तस्करी, ड्रग्स, शस्त्र बिक्री, जाली नोट, महिलाओं को भगाना, जमीन लूटना, मंदिरो जैसे अन्य प्रार्थना स्थलों को क्षति पहुँचाना, स्थानीय मुस्लिम समुदाय में भी दहशत फैलाकर रखना यह करते हुए आगे बढना व अंतत : देश से उस हिस्से को तोडना। बिल्कुल वहीं कहानी कई वर्षो से असम व सीमावर्ती क्षेत्र में यह विदेशी सूत्र चला रहे है। दुर्भाग्य यह है कि अब तक तथाकथित धर्म निरपेक्षता के नाम पर अपनी वोट बैंक की खातिर अल्पसंख्यकों की रक्षा का बहाना देते हुए न तो सीमाओं को ठीक से बंद किया गया, न ही घुसपैठियों की

पहचान करते हुए उन पर कार्यवाही की गयी । परिणाम स्वरुप आज असम की कुल ३ करोड की जनसंख्या में अवैध तरीके से ८० लाख लोगों ने अपना नाम बढा दिया है तथा कई उस प्रयास में कतार में है ।

अभी हाल ही में असम के बोडो क्षेत्र में हुई हिंसा कोई स्थानीय विवाद से उत्पन्न नहीं हुई, अपितु इसी व्यापक षडक्यंत्र के तहत घर एवं खेती की जमीनें हडपने, संरक्षित जंगल के क्षेत्र में भारी कब्जा करने से प्रारंभ हुई । जिसका मुख्य उद्देश्य दहशत फैलाकर अंतत : घुबरी की तरह शेष कोकराझार आदि क्षेत्र से भी बोडो जनजाति को हटाते हुए उस क्षेत्र पर पूरी तरह कब्जा करना था । कश्मीर घाटी की तरह वह लोग जिसमें बोडो, अन्य जनजाति, बांग्ला एवं अन्य भाषी लोग आदि सभी गैर – मुस्लिम लोगों को उस क्षेत्र से भगाने की योजना की शुरुआत थी ।

योजना पुरानी थी, लेकिन अब जनसंख्या का संतुला, लगातार हुई अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण षड्यंत्रकारियों के पक्ष में जा रह है । स्थानीक भारतीय मुस्लिम समुदाय को भी दबाया जा रहा है । इसके प्रभाव में हाल ही में स्थानीय असम मुस्लिम नेताओं कसदाऔं असम गरिया–मुरिया देशी – SADM) द्वारा जारी बयान में यह कहा गया कि, सभी मस्जिदों में बांग्लादेशी मौलवियों को नियुक्त किया जा रहा है, तथा दंगो के पीछे घुबरी के सांसद बदरुदीन अजमल का हाथ है, तथा उसकी घिनौनी देशद्रोही नीति इसका मुख्य कारण है, यह पूरा असम जान रहा है । बदरुदीन अजमल द्वारा घुसपैठियों को अवैध रुप से भारत में प्रवेश कराना, उन्हें जाली पहचान पत्र आदि बनवाने में सहायता करना तथा ऐसे मतदाताओं के आधार पर असम में १२६ सदस्योंवाली विधानसभा में १८ विधायकों के बल पर पूरे दबाव की राजनीति की जा रही है । २००५ में प्रारंभ हुए अपने दल (AIUDF – ऑल इंडिा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फंड) की २००९ में देशभर फैलाने की घोषणा के पश्चात् पूरे देश में फैलाए घुसपैठियों को आधार बनाकर कट्टरपंथियों के साथ मिलकर तनाव उत्पन्न करने का काम वह कर रहा है । इसलिए बदरुदीन अजमल को गिरफ्तार करने की मांग पुरे असम में उठ रही है ।

वैसे केंद्र एवं असम सरकार ने अनावश्यकरुप से बोडो नेता और विधायक री प्रमोद ब्रम्ह को जिस तेज गति से गिरफ्तार किया, वैसी तेज गति अजमल के बारे में नही दिख रही है । बोडो लोगों पर दमन चक्र चलाने की नीति छोडकर वास्तविक अलगाववादी नेता अजमल को गिरफ्तार करना समय की मांग है । कश्मीर में जब परिस्थिति बिगड गयी तथा शेख अब्दुल्ला के देशद्रोही इरादे उजागर हुए तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु ने अपने इस मित्र को अंतत : ८ अगस्त १९५३ में गिर:तार करते हुए लगभग १० वर्ष जेल में रखकर वहाँ की परिस्थिति को नियंत्रण में किया । आज बदरुदीन अजमल को भी तत्काल जेल की सलाखों के पीछे डालकर उसके षडत्र का पर्दाफाश करते हुए असम को बचाने की जरुरत है ।

बदरुदीन अजमल असम के दंगाखोर घुसपैठियों एवं मुंबई में आजाद मैदान के दंगाखोर तथा देशभर में असम एवं पूर्वोत्तर सभी लोगों में दहशत फैलाने वाले यह सब एक षडक्यंत्र का हिस्सा है । इन सभी को एक साथ देखने की जरुरत है ।

साथ ही जो बुद्धिजीवी, राजनैतिक दल, मानवाधिकारवादी, पत्रकार आदि इन सब घटनाओं के सच को तोड – मरोडकर प्रस्तुत करते हुए अलगाववादियों का समर्थन करते है, वह ज्यादा खतरनाक है । क्योंकि वह ऐसा वातावरण तैयार करते है, कि प्रशासन उन पर कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता व घुसपैठिये खुले आम घुमते है । ऐसे लोगों के विरोध में व्यापक जनमत की आवश्यकता है ।

हमारी सेनायें सीमा पर दुश्मनों से लडने में पूरी तरह सक्षम है, लेकिन देश के अंदर के छुपे दुश्मनों को जनता को पहचानना जरुरी है इन्हें हमें रोकना होगा । भ्रामक विचारों का पर्दाफाश हमें करना होगा । इसलिए बोडो या समूचे पूर्वोत्तर के लोगों के प्रति सहानुभूति रखना पर्याप्त नहीं होगा, हम सभी देशवासियों को उससे अधिक सोचने की जरुरत है ।